(b) The requisite information is given below:—

(Rs. in lakhs)

Year	Amount surrendered	
	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
1956-57 .	0·43	2·36
1957-58 .	1·87	11·63
1958-59 .	..	4·69
1959-60 .	0·48	0·22
1960-61 .	0·76	4·90
TOTAL .	3·54	23·80

Loan by L.I.C.

2093. Shri Malaichami: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to issue loans to the Cooperation Central Land Mortgage Bank, Madras, out of the funds of the Life Insurance Corporation of India; and

(b) if so, what is the amount and when it will be given?

The Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). The Life Insurance Corporation of India has decided to subscribe to Debentures of the face value of Rs. 30 lakhs, when issued by the Madras Co-operative Central Land Mortgage Bank.

Land for landless people

2094. Shri Surya Prasad: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that thousands of acres of arable land which was used by the former Indian States for encamping purposes is lying useless; and

(b) if so, whether Government are going to distribute this land among landless people for cultivation?

The Minister of Defence (Shri Krishna Menon): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

जीपों का आयात

२०९५. श्री बाल्मीकी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९४७ से अब तक कितनी जीपें विदेशों से मंगाई गईं ;

(ख) वे किस-किस देश से मंगाई गईं; और

(ग) उन पर लगभग कितना व्यय हुआ ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) संख्या २०८ ।

(ख) इटली, बेलिजियम, यू० के० तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ।

(ग) १३.१६ लाख रुपये ।

इलाहाबाद उच्च-न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे

२०९६. श्री सरजू पाण्डेय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद उच्च-न्यायालय में लगभग ४०,००० मुकदमे बिना निर्णय के पड़े हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनको निबटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) (क) जी हां ।

(ख) हाई कोर्ट में अवशिष्ट (arrears) की समाप्ति के लिये उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं । अतिरिक्त न्यायाधीशों की अब तक छः पदों की मंजूरी दे दी गई है और इस संख्या में और अधिक वृद्धि करने का प्रश्न विचाराधीन है । अन्य किये गये उपाय इस प्रकार हैं :—

(१) कार्य दिवसों की संख्या का बढ़ा कर २१० कर दिया जाना,